

(ग), (घ) और (ङ). इस मंत्रालय की आवास योजनायें अलग अलग राज्य सरकारों की मार्फत क्रियान्वित की जा रही है और मीत्रे इस मंत्रालय द्वारा नहीं। आवेदन के फार्म स्वयं उन राज्य सरकारों द्वारा ही नियत किये जाते हैं।

**मुद्रगालय के कर्मचारियों के सेवा नियम**

१७५२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रगालयों के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा सम्बन्धी नियमों का हिन्दी में अनुवाद कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसके लिये कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) भारत सरकार के मुद्रगालयों के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा सम्बन्धी नियमों का अभी तक हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ है।

(ख) इस काम के लिये किये जाने वाले प्रबन्ध की रूपरेखा राज्य भाषा के बारे में अप्रैल १९६० में जारी किये गये राष्ट्रपति के निदेश में दी गई है।

(ग) इस समय ठीक ठीक कोई ऐसी तिथि सूचित कर पाना सम्भव नहीं है, जिस तक भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा सम्बन्धी नियमों का हिन्दी में अनुवाद कराया जा चुकेगा।

#### Tyres and Tubes

1753. **Shrimati Mafida Ahmed:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state the number of firms granted import licence for tyres and tubes through the State

Trading Corporation in the country during 1959-60?

**The Minister of Commerce (Shri Kanungo):** Import licences for tyres and tubes are issued in the name of the State Trading Corporation with letters of authority in the name of Indian agents of foreign suppliers. So far such letters of authority have been issued in the name of 3 firms only.

#### Rajghat Samadhi Quarters

1754. **Shri Tangamani:** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rent is charged from the Central Public Works Department staff in occupation of Rajghat Samadhi quarters;

(b) whether it is a fact that employees of the Municipal Corporation of Delhi and Rajghat Samadhi Committee who are in occupation of such quarters, are not charged any rent; and

(c) if so, the reasons for discrimination against the Central Public Works Department staff?

**The Minister of Works, Housing and Supply (Shri K. C. Reddy):** (a) and (c). The Rajghat Samadhi quarters have been allotted to a few employees of the Rajghat Samadhi Committee and the C.P.W.D. According to a decision of the Committee, occupation of these quarters is to be rent-free. No rent is, therefore, recovered by the Committee from their employees. Usual recovery, as for Government accommodation, is being made from the Central Public Works Department personnel temporarily serving with the Rajghat Samadhi Committee under the rules normally applicable to Government employees. The whole matter is being reviewed.